

प्रेषक,

आर.डी.पालीवाल,  
सचिव एवं विधि परामर्शी,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाप्रशासक,  
मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 11 जनवरी, 2008

विषय- महाप्रशासक,उत्तराखण्ड की ओर से न्यायालयों में प्रतिनिधित्व एवं पैरवी हेतु अधिवक्तागण का आवन्धन।  
महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-2163/महा0प्रशा0/2007, दिनांक 05-12-07 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि महाप्रशासक,उत्तराखण्ड की ओर से मा. उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में संस्थित अथवा प्रतिरक्षा वाले मामलों में उत्तराखण्ड राज्य की ओर से आवद्ध किये गये मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ता को एवं जिला न्यायालयों में संस्थित मामलों में जिला शासकीय अधिवक्ता(सिविल)/सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) को शासन द्वारा उनके लिए नियत फीस पर पैरवी करने हेतु निदेशित एवं अधिकृत किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में महाप्रशासक यदि उचित समझें तो विशेष अधिवक्ता आवद्ध कर सकते हैं।

भवदीय,

(आर.डी.पालीवाल)  
सचिव ।

संख्या : 1एक(7)/xxxvi(1)(2)/2007

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महाधिवक्ता,मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,परिसर नैनीताल ।
- 2- मुख्य स्थायी अधिवक्ता,मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय परिसर,नैनीताल ।
- 3- समस्त जिला न्यायाधीश,उत्तराखण्ड ।
- 4- समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड ।
- 5- समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता(सिविल), उत्तराखण्ड ।
- 6- एन.आई.सी./गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अलीक कुमार वर्मा)  
अपर सचिव ।